प्रसार भारती

भारतीय प्रसारण निगम

आकाशवाणी केन्द्र शिमला

23.02.2026 / प्रादेशिक समाचार / 18:00बजे

संकल्प योजना

राज्य सरकार ने प्रदेश में मातृ व शिशु के बेहतर स्वास्थ्य और कुपोषण की समस्या के समाधान के लिए 2 सौ 7 करोड़ रूपये से अधिक की लागत से इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि इस योजना के तहत प्रदेश में 2 लाख 99 हज़ार 4 सौ 88 पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं व धातृ माताओं को उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन, आवश्यक कैलोरी और महत्पूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व से युक्त पूरक पोषण उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुपोषण राज्य में एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय है और सरकार इसे समाप्त करने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है।

अमित शाह–भारत टैक्सी

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारत टैक्सी के सारथियों से बातचीत की। आज जारी एक वीडियो में उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी सहकारी समिति का उद्देश्य चालकों को उनके काम का स्वामित्व देकर उन्हें सशक्त बनाना है। अमित शाह ने बताया कि इस पहल का लक्ष्य निजी टैक्सी सेवा कंपनियों से जुड़ी समस्याओं को कम करना और चालकों को काम दिलाना है, न कि सहकारी समिति को। उन्होंने कहा कि यह पहल चालकों के कल्याण और यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक मंच बन रही है।

जगत सिंह नेगी

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि आरडीजी के मुद्दे पर भाजपा हिमाचल के हित में नहीं है। आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद–275–एक के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर और विशेष रूप से अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य को विशेष केंद्रीय सहायता का प्रावधान है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि हिमाचल को तब तक राजस्व घाटा अनुदान मिलना चाहिए, जब तक राज्य की वित्तीय स्थिति संतुलित नहीं हो जाती।

राकेश जमवाल

भाजपा के मुख्य प्रवक्ता व विधायक राकेश जमवाल ने राजस्व मंत्री द्वारा आरडीजी को लेकर दिए गए बयान को उनकी बौखलाहट करार दिया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि राजस्व घाटा अनुदान के विषय पर विधानसभा में 3 दिन चर्चा हुई, जिसका पूरा रिकॉर्ड है। राकेश जमवाल ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार वित्त आयोग के सामने अपना पक्ष प्रभावी ढंग से रखने में नाकाम रही, जिससे आरडीजी बंद हुई है। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग द्वारा इस बारे में संकेत देने के बावजूद कांग्रेस सरकार अपने खर्चों पर लगाम नहीं लगा पाई और अपनी नाकामियों का ठिकरा भाजपा पर फोड़ना चाहती है।

यादविंद्र गोमा

आयुष मंत्री यादविंद्र गोमा ने आज धर्मशाला में ज़िला योजना विकास व 20 सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने पात्र भूमिहीन परिवारों को आवास निर्माण के लिए प्राथमिकता के आधार पर भूमि उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया में तेज़ी लाने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। यादविंद्र गोमा ने कहा कि लंबित आवेदनों का आबंटन मई माह में पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि कांगड़ा ज़िला में 4 सौ 78 भूमिहीन परिवारों को आवास के लिए सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध करवाई गई है। बैठक में खाद्य सुरक्षा योजनाओं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्वास्थ्य सेवाओं व शिक्षा योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई।